POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2024-26 (RNI.REG.NO 39658/1983) #ग्रा.ग./2026/अंक 06

मासिक प्रेषण दि. 8 जून, सी.एस.ओ., आरएमएस, जयपुर

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016

प्रकाशन की तिथि : 01 जून, 2026 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

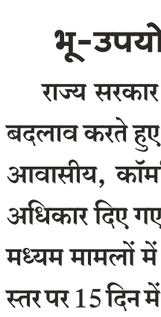

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम!

हर साल 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, क्योंकि पर्यावरण की सुरक्षा पर ही हमारा जीवन सुरक्षित है। सोचिए, आज पीने को शुद्ध जल दुर्लभ है। वन सम्पदा सिमटती जा रही है। वनों के जीव-जन्तु जो प्रकृति की धड़कन हैं, विलुप्त हो रहे हैं। सांसें जहरीली हवा में घुट रही हैं। फिर हम कैसे सुरक्षित रहेंगे?

इस बार का विषय आत्मा को झकझोर देता है। जलवायु परिवर्तन अब आने वाले कल की बात नहीं, आज की कड़वी सच्चाई है। इसके थपेड़े हर घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। हमारी धरती माँ ग्रीनहाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जहरभरे कीटनाशकों एवं रसायनों का बोझ सह नहीं पा रही। हम और हमारी सरकार हर साल करोड़ों वृक्ष लगाने का दावा तो करते हैं, पर उससे अधिक वृक्षों को हम खुद ही उजाड़ देते हैं। वृक्षों की कटाई जलती आग में घी डालने जैसा है।

हम पृथ्वी और पर्यावरण की रक्षा का संकल्प तो लेते हैं, लेकिन लालच और धन कमाने की लालसा हमारे संकल्पों की धज्जियां उड़ाती हैं। हमारे पूर्वज प्रकृति के प्रति समर्पित थे, इसीलिए निरोगी जीवन जिए। आज हम अनेक रोगों से घिरे हैं, स्वास्थ्य डगमगा रहा है। जल का संकट गहरा है, हवा में भी जहर घुला है, प्लास्टिक का उपयोग विकट समस्या बन चुका है।

खुशी है, आज की युवा पीढ़ी इस स्थिति को अधिक महसूस कर रही है, युवा सिर्फ बातें नहीं कर रहे, सार्थक बदलाव की पहल कर रहे हैं। अब हर व्यक्ति, समाज और सरकारें अपनी जिम्मेदारी उठाएं, तभी जाकर हम खुद का और अपनी संतानों का सुरक्षित भविष्य संवार पाएंगे।

राजस्व विभाग ने नियमों में किया बड़ा बदलाव

भू-उपयोग परिवर्तन 30 दिन में, ग्रीन एनर्जी को दी प्राथमिकता

राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि को गैर-कृषि उपयोग में बदलने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए समय सीमा 45 से घटाकर 30 दिन कर दी है। राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में आवासीय, कॉमर्शियल, औद्योगिक व संस्थानिक उपयोग के मामलों में संभागीय आयुक्त को भी अधिकार दिए गए हैं। यह भी स्पष्ट किया गया है कि छोटे मामलों में तहसीलदार व उपखंड अधिकारी, मध्यम मामलों में कलेक्टर और बड़े मामलों में संभागीय आयुक्त या राज्य सरकार अनुमति देगी। इनके स्तर पर 15 दिन में फैसला नहीं होने पर मामला स्वतः कलेक्टर को भेजा जाएगा।

बड़ा बदलाव नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को लेकर है। अब सोलर, विंड, बायोमास, बायोगैस, सीएनजी-सीबीजी, हाइड्रो और बैटरी स्टोरेज जैसे सभी प्रोजेक्ट एक ही श्रेणी 'रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स' में शामिल होंगे। भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क औद्योगिक दर का मात्र 10 प्रतिशत तय किया गया है। न्यूनतम भूमि सीमा 4 हजार से बढ़ाकर 10 हजार वर्गमीटर कर दी गई है। भू-उपयोग परिवर्तन में दी जा रही छूट का दायरा बढ़ा दिया गया है। पहले रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में केवल एससी-एसटी वर्ग को बिना रास्ते के शपथ-पत्र के आधार पर तहसीलदार स्तर पर कन्वर्जन की अनुमति थी, अब यह सुविधा गैर एससी-एसटी आवेदकों को भी मिलेगी।

कोल्ड ड्रिंक में मिली गंदगी, कोका-कोला कंपनी पर लगा जुर्माना

जिला उपभोक्ता आयोग, जैसलमेर में तुषार पुरोहित ने कोका-कोला कंपनी एवं शिवम मार्केटिंग के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया। मामले के अनुसार परिवादी तुषार पुरोहित ने 16 जुलाई 2025 को शिवम मार्केटिंग से 810 रुपए में कोल्ड ड्रिंक ब्रांड माजा का कार्टन खरीदा था। उन्हें कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल में प्लास्टिक का टुकड़ा और गंदगी नजर आई। तुषार पुरोहित ने 20 अगस्त 2025 को कोका-कोला कंपनी एवं शिवम मार्केटिंग के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। जांच में कोल्ड ड्रिंक ब्रांड माजा की पैक बोतल में प्लास्टिक का टुकड़ा व गंदगी के आरोप को सही पाया गया।

मामले की सुनवाई पर कंपनी की ओर से कहा गया कि जूस को बोतल में भरने का पूरा प्रोसेस ऑटोमैटिक होता है। कंपनी की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए यह परिवाद दिया गया है। आयोग ने कंपनी की ओर से दी गई इस दलील को खारिज कर दिया और कहा कि इतनी बड़ी और अंतरराष्ट्रीय स्तर की कंपनी होने के बावजूद पीने योग्य उत्पाद में ऐसा होना गंभीर लापरवाही है। उपभोक्ता आयोग ने कोका-कोला कंपनी पर ढाई लाख रुपए की पैनल्टी लगाई और आदेश दिए कि इसमें से तुषार पुरोहित को 50 हजार रुपए दिए जाए, बाकी 2 लाख रुपए 'राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष' में जमा कराए जाएं।

प्रदेश में 'राजस्थान होम स्टे योजना' लागू

प्रदेश में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' और 'ईज ऑफ लिविंग' की अवधारणा को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए 'राजस्थान होम-स्टे (पेईंग गेस्ट हाउस) योजना-2026' लागू की गई है।

पर्यटन विकास, ग्रामीण आय वृद्धि और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है। भारत सरकार के डिरेगुलेशन 2.0 उपायों और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के अनुरूप योजना को सरलीकृत किया गया है। लाइसेंस प्रक्रिया को आसान व मंजूरी को डिजिटल बनाया गया है। सिंगल-विंडो सिस्टम, कम दस्तावेज और आसान रजिस्ट्रेशन सुविधाएं उपलब्ध होंगी। गृहस्वामी होम-स्टे इकाइयां खोल कर संचालित कर सकेंगे। जिससे छोटे निवेशक, ग्रामीण परिवार और महिला उद्यमी भी पर्यटन से सीधे जुड़ सकेंगे।

योजनाओं की जमीनी स्तर पर परख

प्रदेश में केंद्र व राज्य सरकार जमीनी स्तर पर एमएसएमई उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं के तहत दी जा रही राहतों और सुविधाओं का वास्तविक रूप से कितना फायदा मिल रहा है, इसके लिए महा-लेखापरीक्षक (एजी) ऑडिट करेंगे और दी गई रियायतों, अनुमति, क्लीयरेंस प्रक्रिया तथा सेवाओं के पालन की हकीकत का पता लगाएंगे।

इसके लिए केंद्र सरकार के निर्देश पर उद्योग विभाग और रीको के अधिकारियों के साथ एजी की बैठक भी हो चुकी है। इससे उद्योगों को मिल रही सुविधाओं की सच्चाई स्पष्ट होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी, योजनाओं की कमियां सामने आएंगी, प्रशासकीय प्रक्रियाओं में सुधार होगा और निवेशकों का भरोसा बढ़ सकेगा।

प्रदेश के कृषि बाजार की बढ़ेगी ताकत

प्रदेश में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (ग्राम)-2026 के माध्यम से फूड प्रोसेसिंग उद्योग, एग्रो-पार्क और कृषि क्षेत्र में निवेश के नए द्वार खुल रहे हैं। ग्राम 2026 की अहमदाबाद में हुई इन्वेस्टर मीट के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निवेशकों को आंमत्रित किया, जिसमें डेयरी, फूड-पार्क, फूड प्रोसेसिंग व स्पाइस प्रोसेसिंग सेक्टर से संबंधित एमओयू हुए।

मुख्यमंत्री ने इन्वेस्टर मीट में कहा कि देश में पीएम मोदी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में आधुनिक, तकनीकी और लाभकारी बदलाव तेजी से हो रहे हैं। खेती में हो रही अलग-अलग फसलों की वजह से राजस्थान एग्री बिजनेस का पॉवरहाउस बनेगा। इससे छोटे किसान कृषि बाजार की बड़ी ताकत बन सकेंगे।

विश्व पर्यावरण दिवस 2026

विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए पूरे विश्व में मनाया जाता है। वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने हेतु इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी।

विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2026 की थीम 'जलवायु कार्रवाई' पर केंद्रित है। यह जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तत्काल और ठोस कदम उठाने का आह्वान करता है। अतः सभी स्वयंसेवी संस्थाएं अपने-अपने क्षेत्र में उक्त विषय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर जनसाधारण को जागृत और सचेत करें। कृपया कार्यक्रम की रिपोर्ट 'ग्राम गदर' को अवश्य भिजवाने का कष्ट करें।

लागू होगा वीबी-जी-राम-जी योजना

विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) कानून (वीबी-जी-राम-जी) अगले महीने यानी 1 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही मनरेगा योजना समाप्त हो जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी की है।

सरकार के अनुसार 30 जून तक मनरेगा के तहत चल रहे काम नए ढांचे में शामिल होंगे। ई-केवाईसी से सत्यापित मनरेगा जॉब कार्ड नए 'ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड' जारी होने तक मान्य रहेंगे। ई-केवाईसी लंबित होने पर रोजगार नहीं रुकेगा। भुगतान, शिकायत निवारण, आवंटन नियम जैसे नियमों का मसौदा जल्द जारी होगा।

आपणी बोली नूं मिल्यो मान

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को निर्देश दिया है कि राजस्थानी भाषा को सभी सरकारी व निजी स्कूलों में एक विषय के रूप में पढ़ाने की व्यवस्था कर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति व संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप राजस्थानी मातृभाषा के रूप में चरणबद्ध तरीके से पढ़ाई शुरू करने के लिए नीति बनाए।

कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 26 सितंबर तक शपथ पत्र के साथ पालना रिपोर्ट पेश की जाए। कोर्ट के इस आदेश के बाद से प्रदेश के शिक्षा ढांचे में बड़े बदलाव आने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है, जब बच्चा अपनी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर से पढ़ाई करता है तो भाषा को सीखने की रुचि बढ़ जाती है। राजस्थानी एक मानक भाषा है, जिसमें राज्य की सभी बोलियों का मिश्रण होता है।

प्रदेश में बदलता मानसून का स्वरूप

प्रदेश में जहां एक ओर हरियाली और बारिश बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर मौसम का असंतुलन नई चुनौतियां खड़ी कर रहा है। प्रदेश में बारिश का पैटर्न बदलता जा रहा है। जहां पहले पूर्वी हिस्सों में ज्यादा बारिश होती थी, वहीं अब पश्चिमी जिलों में वृद्धि अधिक दर्ज हो रही है।

पिछले एक दशक से जलवायु परिवर्तन ने पश्चिमी राजस्थान की पारिस्थितिकी को पूरी तरह प्रभावित किया है। जहां रेत थी वहां हरियाली नजर आने लगी है। कृषि क्षेत्र में भी 74 फीसदी की वृद्धि दर्ज हुई है। इस बदलाव ने ईकोसिस्टम को नया रूप दिया है। हालांकि, विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि बढ़ता तापमान, भूजल दोहन व शहरीकरण इस संतुलन को बिगाड़ सकता है। इसलिए भूजल संरक्षण को खास महत्व दिया जाए।

'आपदा मित्र योजना' युवा होंगे ट्रेंड

प्रदेश में बढ़ती प्राकृतिक-औद्योगिक आपदाओं के खतरे के बीच राज्य सरकार अब पूर्व तैयारी की रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। प्रदेश में स्कूलों, अस्पतालों मॉल आदि में 469 मॉक ड्रिल और 1585 जन जागरूकता कार्यक्रम हो चुके हैं। जबकि, 'आपदा मित्र योजना' के तहत 13 जिलों में 4700 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया गया है।

अगले चरण में 12,650 युवाओं को आपदा प्रबंधन की विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। आपदा प्रबंधन विभाग के एसीएस भास्कर ए. सावंत ने कहा कि आकाशीय बिजली, लू, बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि और अग्नि दुर्घटनाएं प्रमुख आपदाएं हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में नई चुनौतियां पैदा हुई है। इसके लिए पूर्व तैयारी और प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना सबसे बड़ी आवश्यकता है।

प्रधानमंत्री की देशवासियों से अपील

पश्चिम एशिया में तनाव और उससे उपजे वैश्विक संघर्षों की वजह से ऊर्जा संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से विदेशी मुद्रा बचाने के लिए सामूहिक प्रयास करने की अपील की है।

उन्होंने कहा है कि वे एक साल तक सोने की खरीद संयम से करें, आवागमन के लिए निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन सेवा का उपयोग करें ताकि पेट्रोल-डीजल बचाया जा सके। हर क्षेत्र में स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएं ...। प्रधानमंत्री की अपील को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। अपील आडम्बरनिष्ठ (दिखावा करने वाले) उपभोग को कम करने, विदेशी मुद्रा बचाने और निर्यात बढ़ाने की सलाह है। यह सर्व विदित है कि किसी भी संकट का निराकरण सामूहिक प्रयासों से जल्द किया जा सकता है।

औद्योगिक निवेश का बना नया केंद्र

केंद्र सरकार की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान ने औद्योगिक निवेश के मामले में देश में 8वें स्थान से तीसरे स्थान पर जगह बना ली है। महाराष्ट्र, गुजरात और एनसीआर से बेहतर कनेक्टिविटी के चलते जयपुर तेजी से एक मजबूत इन्वेस्टमेंट हब के रूप में विकसित हो रहा है।

प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर गंभीरता से काम हो रहा है। वेयरहाउस व फैक्ट्री स्पेस का राज्य नया केंद्र बना है। एक साल में ही करीब 5,000 करोड़ के सौदे हो चुके हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जल्द ही कुछ और बिजनेस ग्रुप जयपुर के आसपास बड़ा निवेश करने वाले हैं।

भारत में चाहिए 'तिलहन क्रांति'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से खाने के तेल का इस्तेमाल कम करने की अपील की है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत पेट्रोल-डीजल के बाद सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा खाद्य तेल खरीदने में करता है।

भारत करीब 60 प्रतिशत खाद्य तेल विदेशों से मंगाता है, जिस पर करीब 18.3 लाख डॉलर यानी 1.61 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। विशेषज्ञों का मानना है हरित क्रांति की तर्ज पर अब तिलहन क्रांति की जरूरत है, ताकि देश खाद्य तेल के मामले में भी आत्मनिर्भर हो सके। राजस्थान इस दिशा में बड़ी भूमिका निभा सकता है। राज्य अभी अपनी जरूरत से लगभग दोगुना तेल पैदा कर रहा है।

सड़क निर्माण में प्रदेश दूसरे स्थान पर

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सर्वाधिक लंबाई की सड़कों के निर्माण और बेहतर गुणवत्ता नियंत्रण की श्रेणियों में राजस्थान को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है।

केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित रजत जयंती समारोह में विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों को सम्मानित किया। प्रदेश की ओर से सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने यह पुरस्कार प्राप्त किया।

कम्पोजिंग एवं लेआउट 'कटपुस' जयपुर

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485